

रजिस्ट्री सं० डी० २२१

REGISTERED No. D. 231



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग — खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ५४१]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 1971/कासिंक 10, 1893

No. 541]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 1971/KARTIKA 10, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह प्रयोग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(GRIH MANTRALAYA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November 1971

S.O. 5012.—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas I, V. V. Giri, President of India, have received a report from the Administrator of the Union territory of Tripura and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that for the proper administration of the Union territory of Tripura it is necessary and expedient to suspend the operation of certain provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), (hereinafter referred to as "the Act"), in relation to that Union territory and make certain incidental and consequential provisions:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby—

- (a) suspend, for a period of four months, in relation to the said Union territory of Tripura, the operation of the following provisions of the Act, namely:—

in section 7, sub-section (1), clause (c) of sub-section (2) and the first proviso to that sub-section, and sub-section (4);

sections 8 to 12 (both inclusive), section 15, section 16, section 22 and
section 25:

so much of sub-section (1) of section 27 as requires the previous approval
of the President:

so much of sub-section (1) of section 30 as requires the previous approval of the President;

Sections 33, 34(2) and 36;

sections 44 and 45;

sub-section (1), and the following provision, namely, "whether taken on the advice of his Ministers or otherwise" in sub-section (2), of section 46; and

so much of section 50 as relates to the Council of Ministers; and

(b) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary and expedient for administering the Union territory of Tripura in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period, namely:—

(i) the Chief Minister and other Ministers appointed under sub-section (1) of section 45 of the Act shall cease to hold office as such;

(ii) in relation to the said Union territory, unless the context otherwise requires, any reference in sections 6, 23, 27 to 31 (both inclusive) and section 49 of the Act to the Administrator shall be construed as a reference to the President and any reference in those sections (except section 6) and in section 48 to the Legislative Assembly of a Union territory by whatever form of words shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed as a reference to Parliament;

(iii) in relation to the said Union territory, the reference to the Legislative Assembly of a Union territory in section 26 shall be construed as including a reference to Parliament

V. V. GIRI,
President.

NEW DELHI-4,
The 1st November, 1971.

[No. F. 10/28/71-SR.]
K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1971

का० प्रा० 5012.—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्व साधारण का जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

यतः मुझे, व० वें० गिरि, भारत के राष्ट्रपति को, त्रिपुरा संघ राजक्षेत्र के प्रशासक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट तथा मुझे प्राप्त अन्य जानकारी पर विचार करने के पश्चात्, मेरा यह समाधान हो गया है कि त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए यह आवश्यक और समीचीन है कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम कहा गया है) के कतिपय उपबन्धों का प्रवर्तन निलम्बित किया जाए और कतिपय आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध बनाए जाएं;

अतः अब, इस अधिनियम का धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा,

(क) इस अधिनियम के निम्नलिखित उपबन्धों का प्रवर्तन उक्त त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में चार मास की अवधि के लिए निलम्बित करता हूँ अर्थात्: -

धारा 7 में, उपधारा (1), उपधारा (2) का खण्ड (ग) और उस उपधारा का प्रथम परन्तुक, और उपधारा (4); धारा 8 से 12 तक (जिनमें दोनों धारा सम्मिलित हैं), धारा 15, धारा 16, धारा 22 और धारा 25; धारा 27 का उपधारा (1) का उतना भाग जिसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन का आवश्यकता होती है; धारा 30 की उपधारा (1) का उतना भाग जिसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है;

धारा 33, 34(2) और 36;

धारा 44 और 45;

धारा 46 की उपधारा (1), और उपधारा 2, में, निम्नलिखित उपबन्ध, अर्थात्,

“क्या अपने मन्त्रियों की सलाह पर या अन्यथा लिया गया”;

और

धारा 50 का उतना भाग जो मन्त्रिपरिषद् से सम्बन्धित है;

और

(ख) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध बनाता हूँ जो मुझे पूर्वोक्त अवधि के दौरान संविधान के अनुच्छेद 239 के उपबन्धों के अनुसार त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हैं; अर्थात्:—

(i) इस अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए मुख्य मन्त्री और अन्य मन्त्री उस हैसियत में अपने पद पर नहीं रहेंगे;

(ii) जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उक्त संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में इस अधिनियम की धारा 6, 23, 27 से 31 तक (जिनमें दोनों धारा सम्मिलित हैं) और धारा 49 में प्रशासक के प्रति किसी निर्देश का अर्थ राष्ट्रपति के प्रति निर्देश लगाया जाएगा और उन धाराओं में (धारा 6 को छोड़ कर) और धारा 48 में किसी संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के प्रति किन्हीं भी शब्दों में निर्देश का जहां तक उसका सम्बन्ध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है अर्थ, संसद के प्रति निर्देश लगाया जाएगा;

(iii) उक्त संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में, किसी संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के प्रति धारा 26 में निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि संसद् के प्रति निर्देश उसके अन्तर्गत है।

नई दिल्ली,

1 नवम्बर, 1971

ब० बे० गिरि,

राष्ट्रपति।

[सं० फा० 10/28/71-एस० आर०]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव।

